

भेजने,

पुनर्वासन प्रशासन
प्रमुख सचिव,
सत्तारंगण शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राज्य सरकार

हरिद्वार, दिनांक 24 अप्रैल, 2005

विषय-सैंट मार्कस बायोटेक को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु सत्तारंगण सरकार के द्वारा कुरुली में कुल 0.1555 हे० भूमि कब की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपकी पत्र संख्या-531/भूमि व्यवस्था-भूमि कब-2005 दिनांक 31 मार्च, 2005 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सैंट मार्कस बायोटेक को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु सत्तारंगण (उपराज्य) जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुसूचन एवं उपाचारण आदेश, 2009) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत सत्तारंगण सरकार के द्वारा कुरुली में कुल 0.1555 हे० भूमि कब करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- कंटा धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमि बन रहेगा और ऐसा भूमि पर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के फर्लेक्टर द्वारा ही स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कब करने के लिये आई होगा।

2- कंटा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बचक या भूमि बचक कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमि अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- कंटा द्वारा कब की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर सत्तारंगण सरकार भूमि के विभाग मिलेन को बंधीकरण की स्थिति से ही जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्तर सत्तारंगण सरकार द्वारा ऐसे मामलों से निम्न लिखित रूप में अभिलेखित किया जायेगा, उसी प्रवीचन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

(2)

नहीं है। यदि यह ऐसा नहीं करता तबना उसा भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कम किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकस, समझर या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शुभ हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूल्यांगी अनुसूचित जनजाति से न हो और अनुसूचित जाति से भूमिपर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से निम्नानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूल्यांगी असंलग्नीय दायित्व वाले भूमिपर न हो।

6- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एनएसएनपीलव्यास)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्विवरण।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव आधुनिक, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- आयुक्त, नदवाल मण्डल, पी.डी।
- 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- श्री एनएसएन खन्ना पुत्र श्री सीएसएन खन्ना वि० 1713/28 प्रथम फ्लोर गंगल बिल्डिंग नं०-2 भारतीय पैलेस दिल्ली।
- 5- निदेशक, एनएसएनपील, उत्तरांचल अभिवादन।
- 6- मास आईस।

आज्ञा,
(सोहन लाल)
अवर सचिव।
2